राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 06.06.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2014 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 06.06.2014 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री एस. एस. मूंदड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री वी.सी श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश; श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एमएफ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्रीमती शिखी शर्मा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड व श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री एस. एस. मूंदड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री वी.सी श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश; श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एमएफ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्रीमती शिखी शर्मा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड व श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

1. प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत -3000- नयी शाखाओं की स्थापना मद में बैंकों द्वारा 15 मई 2014 तक लगभग 69% उपलब्धि हासिल की गयी है तथा शेष कार्य 30.06.2014 तक पूरा करने हेतु बैंक प्रयासरत हैं। यह शाखा विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं व व्यवसायिक दृष्टिकोण को केन्द्रित करते हुए किया गया है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शाखा विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है। प्रदेश में हमारी इस उपलब्धि को सराहा भी गया है।

2. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत -2000- से कम आबादी वाले -76855- गांवों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु तैयार रोडमैप को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार Disaggregation Plan के रूप में -3- वर्षों में विभाजित कर, मार्च 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल आवंटित लक्ष्य -30515- के सापेक्ष -14782- गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार 49% उपलब्धि ही दर्शाता है। निरंतर अनुश्रवण के बावजूद जो बैंक लक्ष्य पूर्ति नहीं कर सके हैं, उनसे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता अपेक्षित है ताकि वर्ष 2014-15 व 2015-16 के सभी लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

3. वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रदेश मे आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 88.52% उपलब्धि हासिल की गयी है। आज यहां वार्षिक ऋण योजना 2014-15 का विमोचन प्रस्तावित है जिसमें बैंकवार/जनपदवार/गतिविधिवार लक्ष्यों की विस्तृत सूचना को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संशोधित प्रारूप के अनुरूप संकलित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। नोडल विभागों व बैंकर्स से अनुरोध है कि त्रैमासिक आधार पर इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त प्रयास करें ताकि शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जायें। जनपद स्तर पर भी DCC & DLRC बैठकों में वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा इन्हीं प्रारूप के अनुसार की जाये, तभी यह सूचना प्रणाली प्रभावी रूप से लागू हो सकेगी।

4. प्रदेश के चयनित -12- जनपदों में ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर से मार्च 2014 तक 3% प्वाइंट की वृद्धि के मद में -11- जनपद 0.79% से 11.06% तक वृद्धि दर्ज किये है। फिर भी प्रदेश का ऋण जमा अनुपात दिसम्बर 2013 के स्तर से 0.90% कम हुआ है जिसका कारण कुछ बैंको के ऋण व जमा अनुपात में हुई व्यापक कमी रही है। बैंको द्वारा राष्ट्रीय मानक के अनुसार लक्ष्य पूर्ति हेतु समग्र प्रयास आवश्यक है।

5. बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार की विशेष पैकेज योजनान्तर्गत बैंको द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 25,000 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पूर्ति हेतु सभी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है ताकि सभी पात्र बुनकरों को इस महत्वपूर्ण योजना का फायदा मिल सके ।

6. विगत बैठक दिनांक 21.02.2014 के उपरान्त प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गयी है जिनका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना रहा। संयोजक बैंक द्वारा बी.जी.आर.ई.आई. की विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक का आयोजन दिनांक 21.03.2014 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, शाखा विस्तार कार्यक्रम, लीड बैंक स्कीम आदि पर दिनांक 28.04.2014 को बैंक नियंत्रकों के साथ एवं 06.05.2014 को बैंक नियंत्रकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ उच्च स्तरीय बैठके आयोजित की गयी। साथ ही प्रदेश में गठित एस.एल.बी.सी. की -5- सब-कमेटीज द्वारा भी नियमित बैठकें की गयी हैं।

अपने सम्बोधन के अन्त में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखो, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यो व उपलब्धियो से सम्बन्धित सुसंगत आकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियो को और प्रभावी रुप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री एस. एस. मूंदड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- विगत 29 मार्च 2013 को प्रदेश में बैंक शाखा विस्तार की जो ऐतिहासिक शुरुआत की गयी थी उसके नतीजे हमारे सामने हैं तथा इस ऐतिहासिक घटना को Limca Book of Records में National Record की हैसियत से स्थान मिला है। इस उपलब्धि हेतु यहाँ सदन में उपस्थित सभी अतिथि साधुवाद व बधाई के पात्र हैं। निश्चय ही यह कार्य प्रदेश शासन, केन्द्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड एवं विभिन्न बैंकों के मध्य परस्पर सामंजस्य एवं प्रगाढ सम्बन्धों की मिसाल है।

- National Council of Applied Economic Research (NCAER) से प्राप्त आकड़ों व अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गयी है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह वृद्धि मुख्यतः मानसून की दशा पर आधारित रहेगी। वर्ष 2013-14 में Index of Industrial Production (IIP) कम हुआ है जिसका कारण Corporate & Infrastructure Development Investments में दर्ज गिरावट है। इसी अवधि के दौरान Exports में 4% की वृद्धि हासिल की गयी है जो विगत वर्ष के मुकाबले काफी बेहतर है।

वर्ष 2014-15 हेतु GDP Growth Rate 5.1 – 5.5% रहने की संभावना व्यक्त की गयी है। साथ ही Wholesale Price Index (WPI) आधारित Inflation Rate 6.1% एवं Fiscal Deficit 4.5% of GDP रहने की संभावना व्यक्त की गयी है।

यह संभावनायें एवं अनुमान हमें इस वित्तीय वर्ष हेतु अपनी रणनीति एवं कार्ययोजना को सही ढंग से क्रियांवयित करने हेतु इंगित करते है।

- गत 15.01.2013 को माननीय गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा 01.01.2013 से 31.03.2014 तक कुल -2003- शाखायें खोली गयी हैं तथा 15.05.2014 तक यह संख्या बढकर -2103- हो गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप बैंकों द्वारा अवशेष सभी चयनित केन्द्रों पर शाखा विस्तार में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है ताकि नियत तिथि 30.06.2014 तक यह कार्य सम्पन्न हो सके।

  साथ ही भारत सरकार द्वारा सभी शाखाओं में ए.टी.एम. स्थापित करने के स्थायी निर्देशों का भी पालन बैंकों द्वारा किया जाना चाहिये जो बैंकों की व्यवसाय वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा तथा Alternate Delivery Channels (ADC) के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में भी सहायता प्रद्रान करेगा।

- प्रदेश में बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदान ऋण तथा कृषि एवं कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत क्रमशः 55.37, 26.15 एवं 21.25 है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों क्रमशः 40%, 18% एवं 10% के सापेक्ष काफी उच्च स्तर पर है। इस क्रम को नियमित रुप से बनाये रखने व वृद्धि हेतु प्रयास जारी रखे जाये।

- भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के क्रियांवयन की सघन समीक्षा की जा रही है। अतः वित्तीय समावेशन को एक व्यापार का अवसर मानकर इसमें अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। समय की जरुरत है कि उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुये अधिक से अधिक संख्या में धनराशि का लेन देन किया जाये। सभी स्टेक होल्डर्स से आग्रह है कि समय बद्ध तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाये ताकि इसका वास्तविक लाभ बैंक के अंतिम लाभ्यार्थियों को प्राप्त हो सके।

- बैंको द्वारा वर्ष 2013-14 में कुल वार्षिक लक्ष्य ₹ 96822.78 करोड़ के सापेक्ष ₹ 85710.51 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो लक्ष्यों का 89% उपलब्धि दर्शाता है। आज वार्षिक ऋण योजना 2014-15 का विमोचन प्रस्तावित है जिसका आकार कुल ₹114931.33 करोड़ है। यह योजना नाबार्ड द्वारा तैयार Potential Linked Plan (₹121618.32 करोड़) का लगभग 95% है तथा वर्ष 2013-14 की वार्षिक ऋण योजना से लगभग 19% वृद्धि दर्शाता है। इस योजना की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु सभी स्तर पर कार्यरत प्रत्येक यूनिट को अपना योगदान करना होगा।

- बैंको द्वारा वर्ष 2013-14 में लगभग 31.20 लाख मामलों में नवीनीकरण तथा 15.88 लाख मामलों में नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की गयी है जो प्रदेश में तैयार विशेष अभियान के अन्तर्गत की जा रही है। सभी स्टेक होल्डर्स इस कार्य हेतु बधाई के पात्र है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानो का कवरेज अनिवार्य है अतः आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात सभी स्तर पर चिंता का विषय है। मार्च 2014 में वाणिज्यिक बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात 52.62% रहा जो माह मार्च 2013 से 3.52% व दिसम्बर 2013 से 0.90% की कमी दर्शाता है। बैंको द्वारा इस ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने हेतु मैं अपना अनुरोध दोहराना चाहूँगा।

अभी भी प्रदेश के -75- में से 16 जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम है। एक पहल के रूप में प्रदेश में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में उप समिति का गठन किया गया है तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन ने 11 जनपदों के जिला मजिस्ट्रेटों को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने हेतु व्यापक निर्देश दिये हैं जो निश्चय ही एक सराहनीय प्रयास है।

दिनांक 15.01.2013 को माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के अनुसार चयनित -12- जनपदों में मार्च 2014 तक मार्च 2013 के स्तर पर ऋण जमा अनुपात को 3% बढ़ाने हेतु निर्णय लिया गया था। यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा कि चयनित -12- में से-6- जनपदों ने दी गयी अवधि में वांछित 3% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है तथा -5- जनपदों ने 0.79% से लेकर 2.91% तक की वृद्धि दर्ज की है।

- विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मार्च 2014 तक कुछ योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। नये वितीय वर्ष 2014-15 हेतु विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हुये है तथा प्रदेश में कार्यरत बैंको व नोडल ऐजेन्सियों का प्रयास होना चाहिये कि सभी आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाये ताकि इन योजनाओं का लाभ टारगेट ग्रुप को प्राप्त हो सके।

- प्रदेश में चयनित -21- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में प्राथमिकता प्राप्त ऋण के सापेक्ष अल्पसंख्यक समुदाय को क्रमशः 30.49% व 20.92% (खाता संख्या व बकाया धनराशि) ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में इन समुदायों को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत क्रमशः 21.52% एवं 17.49% (खाता संख्या व बकाया धनराशि) है।

- प्रदेश में बैंको की ऋण वसूली में गिरावट चिंता का विषय है क्योकि इसके कारण बैंक धनराशि की रीसाइकिलिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- उन्होंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बित सभी मार्जिन मनी खातों में कार्यवाही, बुनकरों हेतु भारत सरकार की विशेष राहत योजना का क्रियान्वयन जिसके अन्तर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जा रहे विशेष कैम्पस का सफल आयोजन, प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदो हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित बी.जी.आर.ई.आई. योजना का प्रभावी क्रियांवयन, शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यो की शत प्रतिशत पूर्ति पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इन सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

श्री आर.एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित), उ. प्र. शासन ने सदन को सम्बोधित करते हुए सभी बैंको द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकों ने Core Banking Solutions को लागू किया तथा इस सी.बी.एस. प्रणाली का फायदा सामान्य जनता को पहुँच रहा है जो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इसमें और अधिक विस्तार की आवश्यकता है।

- -3000- नई बैंक शाखाओं की स्थापना की प्रगति दर्शाती है कि 31.05.2014 तक -2136- शाखाएं बैंकों द्वारा खोली गयी हैं। यद्यपि बैंकों द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है फिर भी असीम सम्भावनाएं व्याप्त हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से अनेक बातें सामने आई हैं जैसे कि अचयनित स्थान पर शाखा की स्थापना, अचयनित जनपदों में शाखा- विस्तार तथा शाखाओं का ऐसे स्थानों पर विस्तार जहाँ का लक्ष्य शून्य

था इत्यादि। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बैंक्स इस दिशा में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए शाखा-विस्तार कार्यक्रम को पूर्ण करें।

उन्होंने बैंकर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में सभी के आपसी सहयोग से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगा।

श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एमएफ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार जो इस बैठक में पहली बार पधारे थे, ने अपने सम्बोधन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला:-

- शाखा-विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत यद्यपि प्रदेश में सराहनीय प्रगति दर्ज की गयी है तथापि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही शाखाओं की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की प्राथमिकता सब-सर्विस एरिया अवधारणा के अनुसार गांवों की आबादी हेतु बैंकिंग सेवाओं का विस्तार है तथा बैंकों द्वारा इस दिशा में प्रयास तेज किये जाने चाहिये ताकि इस कार्यक्रम का क्रियांवयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

- शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मार्च 2009 से पहले के ऐसे खाते जिनमें मार्जिन मनी क्लेम बैंकों द्वारा दर्ज किया जाना अवशेष है, में यह प्रक्रिया 30.06.2014 तक अवश्य पूरी कर ली जाए क्योंकि तदोपरांत इन क्लेम्स का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस योजनांतर्गत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जिनका क्रियांवयन बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये। साथ ही योजनांतर्गत -150- चयनित जनपदों में Interest Subvention के दिशानिर्देश भी निर्गत किये गये हैं जिनका समयबद्ध सीमा के अनुसार अनुपालन बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- सरफेसी ऐक्ट 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करते हुए बैंकों की ऋण-वसूली की स्थिति में व्यापक सुधार की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कुछ निर्देश पुनः राज्य सरकारों को निर्गत किये जा रहे हैं।

- आरसेटी संस्थानों की कार्यप्रणाली का ज़िक्र करते हुए उन्होंने अवगत कराया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकों के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशकों के साथ सम्पन्न बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी तथा बैंक अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि सी एवं डी. श्रेणी में चल रही आरसेटी संसथानों की स्थिति में सुधार करते हुए बैंक इन्हें क्रमशः ए. व बी. श्रेणी में जून 2014 तक लायेंगे। अतः प्रदेश में बैंकों द्वारा अपने सी. व डी. श्रेणी आरसेटी संस्थानों में सुधार किया जाना चाहिये।

- डी.बी.टी.एल. पर चर्चा करते हुए श्री मनीष गुप्ता ने अवगत कराया कि इस प्रणाली की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली को जारी रखने की सिफारिश की है तथा तत्सम्बन्धी निर्देश भारत सरकार द्वारा निकट भविष्य में जारी किये जायेंगे।

- प्रदेश में ऋण-जमानुपात की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि वे सभी बैंक जिनका ऋण-जमानुपात प्रदेश के औसत से कम रहा है, अपनी स्थिति में सुधार करें ताकि कुल मिलाकर प्रदेश की अच्छी स्थिति परिलक्षित हो सके।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एमएफ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश में कार्यरत बैंक्स नये वित्तीय वर्ष में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

श्रीमती शिखी शर्मा, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया :-

- प्रदेश में विद्यमान कोआपरेटिव एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सुदृढ वितीय स्थिति न होने के कारण अधिकांश जिम्मेदारियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से पूरी की जाती हैं। अतः इसमें वांछित सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही साथ सामाजिक उत्थान के एजेण्डा में कोआपरेटिव बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महती भागीदारी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सुदृढ वितीय स्थिति होने पर ही इन बैंकों को बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं।

- प्रदेश में व्याप्त कम ऋण-जमानुपात के संदर्भ में महाप्रबन्धक महोदया ने सुझाव दिया कि बैंकर्स इस कार्य हेतु बड़े कॉरपोरेट खातों तथा अन्य व्यवसाय खातों के अंतर्गत एक संतुलन स्थापित कर कार्यवाही कर सकते हैं।

- प्रदेश में शाखा-विस्तार कार्यक्रम के परिपेक्ष्य में उन्होंने अवगत कराया कि आगामी 10.06.2014 को वाराणासी में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें Wimax कनेक्टिविटी से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा प्रस्तावित है। उन्होंने बैंको के एफ.आई. सर्वर एवं सी.बी.एस. सर्वर का इंटीग्रेशन किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि इसके बिना वितीय समावेशन की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इस दिशा में बैंकों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया :-

- आज लगभग ₹ 115.00 लाख करोड़ की वार्षिक ऋण योजना 2014-15 का विमोचन किया गया है। प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा इन वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक सघन कार्य योजना तैयार करनी चाहिये ताकि लक्ष्य पूर्ति सम्भव हो सके।

- प्रदेश में कम CD Ratio चिंता का विषय है और यह आवश्यक है कि इसमें सुधार लाने हेतु अगले -5- वर्षों की कार्ययोजना तैयार कर क्रियांवयन किया जाये जिससे कि क्रमिक आधार पर वांछित नतीजे प्राप्त किये जा सकें।

- हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव सेक्टर की स्थिति सुदृढ न हो सकने के कारण इसका असर कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इस विषय में प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

- प्रदेश में रोज़गार सृजन एवं युवा वर्ग हेतु उद्यमिता विकास के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रदेश सरकार द्वारा इसका आंकलन करते हुए आंकड़ों की उपलब्धता वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित की जाए ताकि आम जनता को इसकी जानकारी एवं लाभ प्राप्त हो सके।
- कृषि क्षेत्र के व्यापक विस्तार हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियांवयित विभिन्न योजनाओं एवं उनके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं व आकर्षण की जानकारी शासन स्तर से आम जनता को मिल सके व वे लाभांवित हो सके।

- श्री गुप्ता ने वित्तीय साक्षरता हेतु सघन अभियान चलाये जाने की ओर भी इंगित किया। अपने सम्बोधन के अंत में मुख्य महाप्रबन्धक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में विभिन्न विभागों व बैंक स्तर से उच्चतम स्तर की सहभागिता पर बल दिया ताकि विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत निर्णयों हेतु तुरंत कार्यवाही सम्भव हो सके। उन्होंने संस्थागत वित निदेशालय से इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध प्रेषित किया।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरान्त पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 1:-राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 21.02.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विगत बैठक दिनांक 21.02.2014 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत जो सभी सदस्यों को दिनांक 22.03.2014 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या 2:-राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 21.02.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

(I) **प्रदेश के सभी जनपदो में बैको द्वारा आरसेटी संस्थानों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन**

सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल -65- जनपदों में नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -10- अन्य जनपदों में भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। प्रमुख सचिव, संस्थागत वित, श्री आर. एम. श्रीवास्तव ने इस प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया।

(II) **राज्य के शेष सभी जनपदो मे आरसेटी की स्थापना**

पंजाब नैशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक से अनुरोध किया गया कि वे अपने अग्रणी जनपदों यथा बदायूँ, झाँसी तथा शामली एवं सम्भल तथा हापुड क्रमश:, में शीघ्र ही आरसेटी की स्थापना करें। महाप्रबन्धक एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) श्री निर्मेष कुमार ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में स्थापित आरसेटी की सब-कमेटी द्वारा विभिन्न संस्थानों हेतु भूमि आवंटन, निर्माण कार्य व दर्ज प्रगति की विस्तृत समीक्षा अपेक्षित है। त्रैमासिक प्रगति भविष्य में सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

(III) **मार्च 2014 तक प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर पर 3 प्रतिशत प्वाइंटस की वृद्धि**

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार 01.01.2013 से 15.05.2014 तक कुल -2103- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। -10- चयनित जनपदों में ऋण जमा अनुपात में दर्ज की जा रही वृद्धि का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि एक जनपद (बुलन्दशहर) को छोड़कर अन्य -11- जनपदों में इस मानक के अंतर्गत -0.79- प्रतिशत से -11.06- प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इनमें से -6- जनपद ऐसे हैं जहाँ -3%- प्वाइंट के मानक की उपलब्धि सम्भव हो सकी है।

(IV) <u>राज्य के चयनित जनपदो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-एल.पी.जी (डी.बी.टी.एल.) स्कीम का क्रियान्वयन</u>

सदन को अवगत कराया गया कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद शामिल है। बैंको द्वारा विभिन्न मानकों में सराहनीय प्रगति दर्ज की गयी है। केवल आधार सीडिंग कार्य में गति लाने की आवश्यकता है जिसके लिए सम्बन्धित यू.आई.डी.ए.आई. के स्तर पर तेजी लाना अपेक्षित है।

डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत -3- जनपद यथा कानपुर नगर (बैंक ऑफ बड़ौदा), लखनऊ (बैंक ऑफ इण्डिया) एवं इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) चयनित है जहाँ योजना का क्रियांवयन 01.01.2014 से प्रारम्भ किया गया है जिसकी गहन समीक्षा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियमित रुप से की जा रही है। ततक्रम में प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन एवं आयुक्त (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.01.2014 व 27.01.2014 एवं 05.02.2014 क्रमशः समीक्षा बैठके आयोजित की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा इन जनपदों मे योजनांतर्गत सघन समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर "**Oversight Committee**" एवं जनपद स्तर पर "**Implementation Committee**" का गठन किया गया है।

(V) <u>एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उप समितियों द्वारा प्रगति की समयिक रिपोर्टिंग</u>

सदन को अवगत कराया गया कि एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उप समितियां नियमित रुप से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रही है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की उप समिति (संयोजक – भारतीय स्टेट बैंक) की बैठक दिनांक 02.06.2014 को आयोजित की गयी।
2. एन.आर.एल.एम. एवं एस.एच.जी. की उप समिति (संयोजक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा) की बैठक जो दिनांक 19.05.2014 को आयोजित की गयी।
3. आरसेटी की उप समिति (संयोजक – पंजाब नैशनल बैंक) की बैठक दिनांक 20.05.2014 को आयोजित की गयी।
4. कृषि क्षेत्र हेतु गठित उप समिति (संयोजक – यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) की बैठक का आयोजन 30.05.2014 को किया गया।

इन उपसमितियों की बैठक की रिपोर्ट व ऐक्शन प्वाइंट्स सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

(VI) <u>-2000- से कम आबादी वाले सभी -76855- गांवों में मार्च 2016 तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू किया जाना</u>

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा अपने बोर्ड अनुमोदित प्लान 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2013-14 हेतु तैयार प्लान के अनुसार -30515- गांवों को कवर करने के लक्ष्य के सापेक्ष -14782- गांवों को कवर किया गया है जो आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 49% वृद्धि दर्शाता है।

श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0 प्र0 ने चर्चा के दौरान कहा कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ हमें गत् वर्ष (2013-14) के अवशेष लक्ष्यों की पूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी जो निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय एवं भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की शिथिल प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी है।

(VII) **बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना**

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(VIII) **बैंक शाखाओं की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना**

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराकर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या 3:- वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत प्रगति

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। 2000 से कम आबादी वाले चयनित -76855- गॉवों मे बैंकिंग सुविधाओ के विस्तार हेतु बैंको द्वारा बोर्ड एप्रूव्ड प्लान (वार्षिक आधार पर) तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके है। वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य -30515- के सापेक्ष त्रैमास मार्च 2014 तक -14782- गॉवों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है।

सदन को अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2014 को प्रदेश के सभी बैंक प्रमुखों एवं दिनांक 6 मई 2014 को सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति हेतु सतत् प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित -6- जनपदों यथा इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बडौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा की गयी।

विगत् 15.01.2013 को डॉ0 डी. सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के निर्णयानुसार प्रदेश में -3000- नई शाखाएं खोलने के कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गई, जिसके अनुसार 15.05.2014 तक -2103- शाखाएं खोली गयी हैं।

सभी बैंक के नियंत्रकों ने सदन को आश्वासन दिया कि वे अधिकाधिक शाखाएं खोलने हेतु प्रयासरत है। इस क्रम में कुछ बैंकों ने विद्युत आपूर्ति, कनेक्टिविटी तथा उचित परिसर न मिल पाने जैसी आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

कार्यसूची संख्या 4:- हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन

योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 5:- वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रगति समीक्षा

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत मार्च 2014 तक बैंको द्वारा दर्ज की गयी कुल प्रगति 88.52% रही है जो विगत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (87.89%) की तुलना में

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल कार्यालय ZONAL OFF. (E.UP ZONE) लखनऊ

अधिक है। सेक्टरवार कृषि, लघु उद्यम एवं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज प्रगति क्रमशः 80.71%, 146.58% व 72.99% रही है।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति में सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके योगदान से प्रदेश का कुल उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी क्रम मे कुछ अन्य बैंक जिनकी प्रतिशत उपलब्धि, राज्य के कुल उपलब्धि प्रतिशत के सापेक्ष कम रही है, की भी समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा शत प्रतिशत उपलब्धियाँ हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2014-15 का भी विमोचन किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि यह योजना विभिन्न अग्रणी बैंको से उनके अग्रणी जनपदों द्वारा तैयार एवं हमें प्रेषित सूचना के आधार पर समेंकित की गयी है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा- निर्देशों व नाबार्ड द्वारा तैयार पी.एल.पी. पर आधारित है। इस योजना का आकार ₹1,14,931.33 करोड़ है तथा यह गत वर्ष हेतु तैयार योजना के सापेक्ष 19% अधिक हैं।

कार्यसूची संख्या 6:- <u>ऋण जमा अनुपात</u>

बैठक में ऋण जमा अनुपात की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मार्च'2014 तक का ऋण जमा अनुपात विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष क्रमशः 3.52% व ऋण : निवेश + जमा अनुपात 1.55% घटा है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि गत् तिमाही के अंत में -18- जनपदों की संख्या घटकर अब -16- रह गयी है जो बैंकों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे सघन प्रयासों का परिचायक है। कतिपय बैंक जिनके ऋण एवं जमा आंकड़ों में प्रमुख अंतर आने के कारण प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनको अपने आंकड़ों का पुनः अवलोकन करने एवं आवश्यक सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश की प्रगति का सही आंकलन किया जा सके। यह भी अवगत कराया गया कि ऋण जमा अनुपात की सघन समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय मे एक उप-समिति गठित है तथा इसकी नियमित बैठके होती है।

प्रदेश मे चयनित ऐसे -12- जनपद जिनमें मार्च'2013 के स्तर से मार्च'2014 तक 3% प्वांइट की वृद्धि का चयन किया गया था, में से केवल -1- जनपद (बुलन्दशहर) को छोडकर अन्य सभी -11- जनपदों में वृद्धि दर्ज की गयी हैं एवं -6- जनपद ऐसे हैं जहाँ इस मानक की पूर्ति सम्भव हो सकी।

कार्यसूची संख्या 7:- <u>प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा</u>

सदन को अवगत कराया गया कि इस योजनान्तर्गत हमारे प्रदेश में अच्छी उपलब्धि दर्ज की गयी है तथा एक मूल्यांकन/ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इन जनपदों में कृषि उत्पाद व उत्पादकता मे वृद्धि दर्ज की गयी है।

सचिव (कृषि एवं सहकारिता), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार हमारे प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक का आयोजन दिनांक 21.03.2014 को किया गया। महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), श्री निर्मेष कुमार ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जिसके अनुसारप्रदेश में बी.जी.आर.ई.आई. की एक उप-समिति यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में गठित है। अब इस उप-समिति की बैठक में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा नियमित रुप से की जाती है। इस उपसमिति की -8- बैठके अभी तक की जा चुकी है।

कार्यसूची संख्या 8:- <u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र परंतु वंचित किसानों को आच्छादित किया जाना</u>

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

नवीन कृषि बीमा योजना की चर्चा करते हुये सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध किया कि योजना के अंतर्गत सभी दिशा निर्देशों का ससमय पालन करे तथा इसका वृहद प्रचार-प्रसार करते हुये ग्रामीण केन्द्रों/बैंक शाखाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को जागरुक करे ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यसूची संख्या 9:- <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंको की मार्च'2014 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 10:- <u>साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह</u>

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अंतर्गत मार्च'2014 तक की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि इस योजना में सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिये ताकि गरीब एवं कमजोर वर्ग को साहुकारी ऋणों से मुक्ति दिलायी जा सके।

कार्यसूची संख्या 11:- <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत व गैर निष्पादक आस्तियो के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति</u>

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदत्त सहयोग की सराहना सदन द्वारा की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया। बैंको से यह भी अनुरोध किया गया कि लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो का विवरण ऑन लाइन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करें एवं नियमित रुप से अपडेट करें।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने शासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वाशन देते हुये कहा कि इस विषय पर माननीय मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी किया जा चुका है। वसूली कैम्पों के माध्यम से अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित की जा सकती है। इसी क्रम में उन्होने कहा कि बैंको तथा राजस्व विभाग के ऑकड़ो का मिलान अनिवार्य है।

कार्यसूची संख्या 12:- <u>अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की मार्च'2014 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। साथ ही चयनित -21- जनपदों की विस्तृत सूचना प्रेषण हेतु बैंको से अनुरोध किया गया।

बैंको से सही डाटा रिपोर्टिंग हेतु अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या 13:- <u>स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)</u>

प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों की आलोच्य अवधि एवं योजना के प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 14:-<u>विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगारपरक कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा</u>

(क) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :</u>

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्वरूप बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रदेश के चयनित -22- जनपदों के -22- विकास खण्डों में **intensive** आधार पर वर्ष 2013-14 से क्रियांवयन किया जा रहा हैं।

चर्चा के दौरान श्रीमती उर्वशी प्रसाद, सी.ओ.ओ., एस.आर.एल.एम., उत्तर प्रदेश ने अवगत कराया कि इस योजना की सघन समीक्षा के उद्देश्य से एवं भारत सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक उप समिति का गठन बैंक ऑफ बड़ौदा के समंवय में किया जा चुका है जिमकी नियमित बैंठकें आयोजित की जा रही हैं। गत् 19.05.2014 को इस उप-समिति की बैठक में योजनांतर्गत विभिन्न मुद्दों यथा स्वयं सहायता समूहों हेतु समान आवेदन पत्र, दस्तावेजीकरण, समीक्षा प्रणाली व **Interest Subvention** इत्यादि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु नये समूह खाते खोलने का कुल लक्ष्य -24500- रखा गया है जिसका जनपदवार आवंटन किया जा रहा है।

डॉ0 फरीद रिज़वी, संयुक्त मिशन निदेशक, एस.आर.एल.एम., उत्तर प्रदेश ने बताया कि आरसेटी संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया बचे हुए -10- में से -8- जनपदों में करने हेतु विभागीय प्रक्रिया की जा चुकी है तथा कैबिनेट की मंजूरी हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है। -2- अन्य जनपदों यथा आगरा एवं गाज़ियाबाद में आरसेटी हेतु भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कार्यरत संस्थान आवंटित भूमि पर स्थापित हैं।

इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश में एस.एल.बी.सी. के संयोजक के रूप में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये एफ.एल.सी. मैटेरियल की प्रिंटिंग प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी हैं तथा आगामी माह के अंत तक इसका वितरण भी प्रारम्भ हो जायेगा।

(ख) <u>स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की मार्च त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी।

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से यह योजना अपने नये स्वरूप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission) के नाम से क्रियांवयित की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य सभी सम्बन्धित को प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया जा चुका है तथा अनुरोध दोहराया गया कि बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों द्वारा विस्तृत जानकारी अपनी सम्बन्धित शाखाओं/कार्यालयों को प्रेषित की जाये।

(ग) <u>प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की मार्च 2014 एवं अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान श्री बी. आर. पटेल, सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस एल बी सी ने सूचित किया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु नोडल एजेंसी से प्रदेश का कुल मार्जिन मनी का लक्ष्य ₹ 173.00 करोड़ प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष तीनों कार्यरत एजेंसी- केवीआईसी, केवीआईवी एवं डीआईसी द्वारा जनपदवार लक्ष्य आवंटित कर

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0

उसकी प्रति हमें अनुमोदनार्थ प्रेषित की है। योजनांतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में यह अपेक्षित है कि इस फोरम द्वारा इन वार्षिक लक्ष्यों का अनुमोदन किया जाए। तदनुसार सदन से अनुरोध है कि इन वार्षिक लक्ष्यों का अनुमोदन करने का कष्ट करें साथ ही साथ इन आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायें।

श्री गुलाम हुसैन, राज्य निदेशक, केवीआईसी, लखनऊ ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदेश को आवंटित मार्जिन मनी लक्ष्य ₹137 करोड़ की पूर्ति बैंकों द्वारा कर ली गयी है तथा इस योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा प्रदान सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा। उन्होंने निवेदन किया कि बैंक शाखाओं तथा सम्बन्धित नोडल बैंक शाखा के मध्य आपसी सामंजस्य और बेहतर किया जाना आवश्यक है ताकि मार्जिन-मनी क्लेम्स का शीघ्रतम निस्तारण सम्भव हो सके। श्री गुलाम हुसैन ने यह भी बताया कि चालू वित्तीय वर्ष हेतु इस योजना के क्रियांवयन से सम्बन्धित -100- दिवसीय कार्ययोजना प्राप्त हुई है जिसके अनुरूप सभी सम्बन्धित द्वारा वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

(घ) <u>सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):</u>

इस योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। श्री एस. सी. वर्मा, प्रबन्धक, सघन मिनी डेयरी परियोजना ने बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की तथा लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने का आग्रह किया।

(च) <u>विशेष समन्वित योजना</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान विभाग से अनुरोध किया गया कि बड़ी संख्या में वापस व निरस्त किये जा रहे आवेदन पत्रों की स्थिति में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि बैंकों को प्रेषित किये जा रहे आवेदन पत्रों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जाये तथा केवल पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन पत्र ही तैयार कर शाखाओं को प्रेषित किये जायें।

(छ) <u>मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की मार्च त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी।

(ज) <u>पशुपालन एवं कुक्कुट पालन योजनायें</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की मार्च त्रैमासांत की प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 15:- <u>भारत सरकार की नवीन योजनायें</u>

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित नवीन योजनाओं यथा एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिज़नेस केन्द्र, ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचलित योजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 16:- <u>शिक्षा ऋण</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की मार्च त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी जिसके अनुसार प्रदेश में बैंकों ने आवंटित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की है जो हर्ष का विषय है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE) LKO.

कार्यसूची संख्या 17:- <u>बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले</u>

सदन को अवगत कराया गया कि इस त्रैमास में दो घटनाएँ घटित हुई जो प्रथमा बैंक से सम्बन्धित हैं, सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी।

इसी क्रम में सदन में उपस्थित पुलिस अधिकारी ने सभी को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी जनपदों में क्राइम ब्रांच गठित की गई हैं जो कि बैंक सम्बन्धित सभी मामलों के लिये नोडल एजेंसी का कार्य कर रही हैं तथा बैंक सम्बन्धी सभी मामलें समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने इससे सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देशों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0 प्र0 के माध्यम से सभी बैंकों को जारी करने की अपेक्षा की।

इस सभा के अंत में श्री रोशन शर्मा, उप महाप्रबन्धक, देना बैंक, लखनऊ ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 06.06.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

SN	Issue	Status	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in remaining -10- Districts of the State.**	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs mostly in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -65- Districts so far. During the Meeting it was deliberated by the State Government that the State Govt. is in the process of allotment of land in another -8- Districts for which the necessary process is on. Ot was also informed that in respect of remaning -2- Districts ie; Ghaziabad & Agra the respective RSETIs are working in the alloted Buildings hence, there is no need for land allotment. It was also desired that in respect of -65- Districts where the land allotment has been made, the Banks must start the process of getting the lease execution, signing of MoU and construction of the building etc. so that the RSETIs may start functioning in its own building and the very purpose of RSETIs is served.	As discussed during the Meeting, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in remaining -8- Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. All the Lead Banks are also requested to ensure that the necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that the RSETIs may start functioning in their own buildings at the earliest. Further the Convenor of the Sub – Committee on RSETIs, ie; Punjab National Bank should also start Reviewing the RSETI wise status of Land allocation, lease execution, signing of MoU and construction of the building etc. **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP, PNB & the Lead Banks)**
2.	**Setting up of RSETIs in all remaining Districts of the State**	During the Meeting it was observed by the house that -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts as per resolution of the SLBC. Viz. Punjab National Bank (Badaun, Jhansi & Shamli), and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur).	Both the Lead Banks are once again requested to ensure establishment of RSETIs in their respective Lead Districts at the earliest. **(Action : Punjab National Bank & Syndicate Bank)**
3	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by the Banks as per Roadmap for March 2014.**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014. As at 31.07.2014 as many as -2307- new B&M Branches have been established by various Banks in the State. The house was also informed that the DIF, GoUP and SLBC (UP) are periodically reviewing the progress with all concerned. A special Review Meeting of Senior Bankers has also been organised for the purpose on 22.02.2014 under the Chairmanship of Chief Secretary, GoUP wherein the Bank wise position was reviewed and it was decided that the timelimit for this Branch expansion Plan should be extended upto 30.06.2014. Accordingly, the Banks are required to open the branches as per their Gaps.	The Banks are required to follow up the set extended deadline to achieve the set targets. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the Monthly and Quarterly progress is advised to the DIF, GoUP & SLBC (UP) on regular basis by all Banks so that the State progress may be highlighted at various forums. **(Action : All Banks & State Government)**

4.	**Coverage of all - 76855-villages having polulation less than 2000 by March 2016 in phased manner**	It was informed that the Board approved Disaggregation Plan for 2013-14, 2014-15 & 2015-16 has been prepared and submitted to Reserve Bank of India by all Banks. As per plan for fiscal 2013-14 - 30515- villages are to be covered against which as at March 2014, -14782- villages have been covered by all Banks which is 49% of the Annual Target. The RBI & the MoF, Govt. of India have expressed concern on the poor performance of the State & has desired the need for urgent improvement and attainment of the set targets as at March 2014. It is pertinent to mention that the Regional Director, RBI had convened -2- rounds of Meetings with the Bank Controllers and the LDMs on 28.04.2014 & 06.05.2014 respectively. State Bank of India, the convenor of Sub – Committee of SLBC on FIP has also convened -5- Meetings for review of FIP Progress	All Banks should ensure coverage of the villages as per yearly set Targets & regular progress should be advised to all concerned on prescribed Annexure- B. **(Action : All Banks)**
5.	**Recapitalization of RRBs – The Baroda U.P. Gramin Bank**	In terms of the recommendations of Dr. K. C. Chakrabarty report, -2- RRBs viz. Baroda U.P. Gramin Bank, Raebareli & Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri, were identified for recapitalization assistance by GoI. Board of Directors of the Bank - BUPGB have in principle agreed to release its share of `29.75 crore and the State Govt. share to the tune of `12.75 crore is required to be released to BUPGB. The matter is being regularly discussed by the concerned Bank with the State Govt. and also during SLBC Meetings. As per the discussions during the Meeting, it was informed by DIF that the matter is under active considetation of the Govt.	The State Govt. is requested to settle this issue at the earliest by releasing its share to BUPGB under the recapitalization Plan of GoI. **(Action : DIF, GoUP)**
6.	**Implementation of PMEGP 2014-15 and Settlement of Margin Money Claims under Scheme**	During the discussions State Director KVIC, informed that there is a gap in settlement of the Claims at Nodal Branch Level which are forwarded to them from the Fianancing branches of the Banks, identified and allocated to them. A request has been made for expeditious disposal of the Claims so that Margin Money allocation Targets set for the State are met with & are achieved.	The Banks should endevour to follow the -100- day Plan proposed by the Nodal Agency for implementation of PMEGP 2014-15. Further, the necessary action must be initiated by the Banks / identified Nodal Branches for expeditious settlement of the Claims under the Scheme as per laid down procedure. **(Action : All Banks)**

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 06.06.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participatio	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	E- Mail IDs
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Chairman & Managing Director	Shri S S Mundra	022- 66985888	
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Nirmesh Kumar	0522-6677607	
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	General Manager (In-charge)	Smt Shikhi Sharma		shikhi.sharma@rbi.org.in
4				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328	skverma1@rbi.org.in
5				Asstt. Gen. Manager	Shri B S Dhruw	9889635394	bsdhruw@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri K K Gupta	9453004901	lucknow@nabard.org
7				Asstt. General Manager	Ms. Anuradha Saxena	9956825672	a.saxena@nabard.org
8	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing	No	Dy. General Manager	Ms Srabani Das	9972531772	sdas@sidbi.in
9	State Bank of India, Lucknow	Chief Gen. Manager	No	Dy. General Manager	Shri V.S. Negi	7408411286	dgmasu1.lholuc@sbi.co.in
10		Gen. Manager	No	Asstt. General Manager	Shri B N Tandon	7408433889	agmlb.lholuc@sbi.co.in
11	Punjab National Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Y P Barar	9198689898	fgmlck@pnb.co.in
12				Asstt. General Manager	Shri M C Madan	8173000101	mcmadan@pnb.co.in
13				Chief Manager	Shri Ashwani Kumar Singh	8004920953	aksingh@pnb.co.in
14	Allahabad Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Ajay Kr. Srivastava	8400339988	
15				Asstt. General Manager	Shri D S Bhatnagar	9984023265	
16				Senior Manager	Shri Ram Khelawan	9452258007	
17	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri L D Rewatkar	9721777711	
18				Senior Manager	Shri Moti Lal	9918702102	
19	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager / State Head	Yes	General Manager	Shri S. K. Mathur	9936406606	mathursk@canarabank.com
20				Divisional Manager	Shri Amar Nath Mondal	9565678880	amarnathmondal@canarabank.com
21	Syndicate Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S K Baghel	8005493987	fgmo_lucknow@syndicatebank.co.in
22				Sr. Manager	Shri K M Saxena	9415004955	
23	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Sunil Vohra	9628368858	sunil.vohra@bankofindia.co.in
24				Sr. Manager	Shri Dinesh Kukreti	9557717535	lucknow.afd@bankofindia.co.in
25	Central Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Asstt. General Manager	Shri M S Bisht	9918001103	agmlucknow@centralbank.co.in
26				DCD-RD	A K Pandit	9628722111	rdluckzo@centralbank.co.in
27	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Vinay Verma	9793205559	zoluck@andhrabank.co.in
28	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Zonal Manager	Shri K L Narang	8416963063	zmlucknow@mahabank.co.in
29	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Asstt. General Manager	Shri Vijay Kr. Uppal	9839226021	
30	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Roshan Sharma	9838851999	roshansharma@denabank.co.in

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 06.06.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participatio	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	E- Mail IDs
31				Manager	Shiv Sagar Chaurasia	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
32	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri. A. K. Bajpai	9839016070	zolucknow@indianbank.co.in
33				Manager (Agri)	Shri Jitendra Singh	9598059588	
34	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State	Yes	Chief Regional Manager	Shri Hari Babu Shukla	9648491480	regmgr@lucsco.iobnet.co.in
35				Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722	adv@lucsco.iobnet.co.in
36	Oriental Bank of Commerce, Lko.	General Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Raj Kumar Arora	8853099002	
37				Chief Manager	Shri Govind Mishra		rh_lko@obc.co.in
38	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Mukesh Nigam	8874209217	zo.lucknow@psb.org.in
39	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Parijat Saurabh	9999935553	agm2del@sbbj.co.in
40				Chief Manager	Shri Sanjay Kumar Gautam	9167499114	skgautam@sbbj.co.in
41	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	Yes	Branch Manager	Shri Sanjay Shukla	9889893331	vipulkhand@sbm.co.in; sanjay.shukla@sbm.co.in
42	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	yes	Dy. General Manager	Shri P K Roy	9695686699	dgmlko@sbp.co.in
43				Sr. Manager	Shri Amit Kumar Sinha	9956283366	anil.kumar.sinha@sbi.co.in
44	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	yes	Chief Manager	Sri Chandra Mohan K. B.	9446500371	lucknow@sbt.co.in
45	UCO Bank, Lucknow	General Manager	No	Dy. General Manager	Shri S. Satapathy	8687755066	fgm.lucknow@ucobank.co.in
46	United Bank of India, Lucknow	Chief Regional Manager	No	Dy. General Manager	Shri Vinod Kr. Babbar	9935011116	
47	Vijaya Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager	Yes	General Manager	Shri A K. Das	9935057850	rmrolucknow@vijayabank.co.in
48	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S Gaur	9415113553	gaurs6696@yahoo.com
49	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri J S Ravi Kumar	7388899777	chmn@aryavart-rrb.com
50				Secretary to Chairman	Shri Rahul Tandon	7388899774	chmsec@aryavart-rrb.com
51				Chief Manager	Shri A K Verma	7388899783	adv@aryavart-rrb.com
52	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri K R Kanojia	8765956232	bupgbrrb@bankofbaroda.com
53	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	kgsg@kgsgbank.co.in
54	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri. B. K. Pandit	9837036728	bijoy.pandit@yahoo.co.in
55	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rakesh Gupta	9415210544	
56	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D S Bainola	7895007722	cms@upgb.com
57	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank	Chief General Manager	Yes	General Manager	Shri. Ajay Pal Singh	9408407381	singh.ajaypal@rediffmail.com
58	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	CGM	Shri. R. K. Singh	9450133699	
59	Axis Bank, Lucknow	Circle Head	Yes	Regional Manager	Mohd Naved Alam	9670888802	mohd.navedalam@axisbank.com
60				Asstt. Vice President	Shri Gautam Mohan Iyer	9198085555	gautam.iyer@axisbank.com

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 06.06.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participatio	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	E- Mail IDs
61				Senior Manager	Shri. Yusuf Khalil	8874223666	yusufkhalil@rediffmail.com
62	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcbank.com
63				Chief Manager	Shri Anuj Raj	7499986270	anuj raj@hdfcbank.com
64	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Head - Retail	Shri Saif Kazmi	8003495394	
65				Regional Relationship Manager	Ms Misha Dua	8953990809	misha.dua@icicibank.com
66	IDBI Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Gyanendra Chaudhary	9559308787	gk.chaudhary@idbi.co.in
67	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	Sr. Vice President	Shri Himanshu Mishra	9554888806	himanshu.mishra@indusind.com
68				Regional Head	Ms Pallvi Singh	9721572057	pallvi.singh@indusind.com
69	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
70	Kotak Mahindra Bank, Mumbai	State Head	No	Asso. Vice President	Shri Ajit Bajpai	9721455135	ajit.bajpai@kotak.com
71	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri. Joy K.O.	7275488057	lkw@federalbank.co.in
72	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asso. Vice President	Shri S.C. Joshi	8009241100	lucknow@nanitalbank.co.in
73	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Manager	Shri Udil Jain	8765155008	br0444@sib.co.in
74	Govt. of U.P.	Chief Secretary	No				
75	Institutional Finance	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri R M Srivastava, IAS	9454417401	aaremes@yahoo.com
76	MSME	Secretary, GoUP	No	Asstt. Director	Shri J N S Yadav	9452240045	jnsy54@rediffmail.com
77	Board of Revenue	Commissioner & Secretary,	No	Special Executive	Shri Rajiv Kumar Shukla	9839410444	rajul444@gmail.com
78	Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Jt. Director	Shri K P Mishra		
79	Rural Development	Commissioner, GoUP	No	Special Secretary	Shri Ashok Kumar	9454413811	
80				COO, UPSRLM	Ms Urvashi Prasad	9560319317	cooupsrlm@gmail.com
81				Jt. Mission Director	Dr. Farid Rizvi	9415169220	mdsrlmup9@gmail.com
82	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri Vimal Chandra Srivastava	9415327130	
83	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director	No				
84		Addl. Director	Yes	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102888	
85				Dy. Director	Dr. Suman Srivastava	0522-4026354	ad.difbanking@gmail.com
86				ARO	Shri Vivek Anand	9808913076	director.dif@gmail.com
87				Jt. Director	Shri R K Gupta	9235629339	jdastatdas@gmail.com
88	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	Director	Shri G Hussain	7523907666	
89				Asstt. Director	Shri V. P. Gupta	9415059359	kvic.lko2011@gmail.com
90				Superintendent	Shri Subodh Kumar	9415463217	kvic.lko2011@gmail.com
91	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri G K Trivedi	7408410717	ceoupkvib@gmail.com
92				Coop. Inspector	Shri P N Singh	7408410736	

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 06.06.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participatio	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	E- Mail IDs
93	Saghan Mini Dairy Pariyojana	General Manager	No	Manager	Shri S C Verma	9621874616	pcdfsmdp@yahoo co in
94	Police Headquarter	Director General	No	S P (Crime)	Shri Sabha Raj	9454401144	
95	Ministry of Finance, GoI	Director (CP & MF)	Yes	Director (CP & MF)	Shri Manish Gupta	9650503560	manish gupta70@nic in
96	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Regional Manager	Shri Gaurav Singh	7408339413	gauravs@aicofindia com
97	Special Invitee						
98	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Jt. Director	Shri S K Saxena	9415956850	sksaxena9620@gmail com
99				Jt. Director (Poultry)	Dr. S P Singh	9415361292	
100				Jt. Director	Dr. Anandeshwari Awasthi	9935299954	anandeshwariawasthi@gmail com
101	UPMA	CEO	Yes	CEO	Shri. Gyan Prakash	9918846003	gyanp upma@gmail com
102				Dy. CEO	shri. Sudhir Sinha	9415222872	sinhasudhir53@gmail com
103	Convener Bank - Bank of Baroda			General Manager	Shri H S Kler	9568042211	dgm upu@bankofbaroda com
104				Dy. Gen. Manager	Shri R K Awasthi	9919908444	
105				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singla	9839112344	
106				Asstt Gen. Manager	Shri B R Patel	0522-6677722	
107				Chief Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	
108				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
109				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730	
110				Manager	Ms Silk Smita	0522-6677694	
111				SWO	Ms Preeti Arya	0522-6677726	
112				SWO	Ms Anjali Singh	0522-6677726	